संस्कृत दिवसपर विशेष

बिहारमें संस्कृत-शिक्षाका मखौल

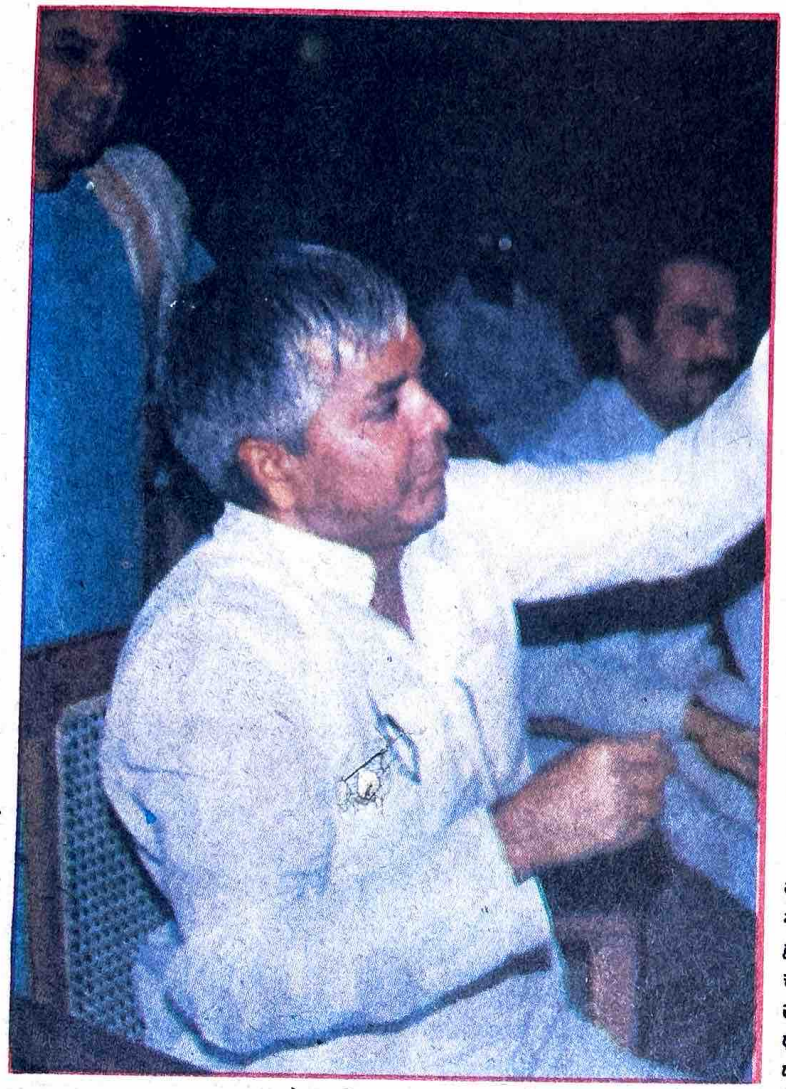

यों तो बिहारमें शिक्षाकी बात करना ही अपने आपमें एक मजाक बन गया है क्योंकि पिछले २० वर्षोंसे सबसे ज्यादा अव्यवस्था और अराजकता यहांके स्कूलों और कालेजोंमें व्याप्त है। इसका खामियाजा मुख्य रूपसे उन अभिभावकोंको भुगतना पड़ रहा है जो पैसेके अभावमें अपने बच्चोंको बिहारसे बाहर भेजनेमें असमर्थ हैं। खासकर वैसे अभिभावकोंकी स्थिति तो और भी हास्यास्पद है जो यहांके स्कूलोंमें भी अपने बच्चोंको नहीं पढ़ा पाते। ऐसे ही बच्चोंके भविष्यका रोना रो रहे हैं बिहारके ३७७६ संस्कृत विद्यालय जिनके पास अपना मकान नहीं है और इन विद्यालयोंके नाम हताशामें जी रहे १४,००० शिक्षक, जिन्हें १४ वर्षोंसे वेतन नहीं मिला है। संस्कृत शिक्षकोंका आरोप है कि वेतन देनेकी बात तो दूर, उल्टे मुख्य मन्त्री लालूप्रसाद सार्वजनिक रूपसे उन्हें अपमानित करने और उनका मनोबल गिरानेका कोई अवसर नहीं चूकते। संस्कृतको वे ब्राह्मणोंकी भाषा मानते हैं और जनसभाओंमें ब्राह्मणवादी व्यवस्थाका विरोध करनेके नामपर ब्राह्मणोंके खिलाफ अपशब्द बोलना लालूप्रसादकी आदतोंमें है। इसलिए संस्कृत शिक्षकोंका प्रतिनिधिमण्डल जब भी मुख्य मन्त्रीसे मिलने जाता है तो सम्बोधनकी शुरुआत शिक्षकोंके चन्दन टीकापर व्यंग्यात्मक टिप्पणीसे होती है- 'क्या टीकाधारी, तुम लोगोंको वेतन नहीं मिला? ठीक है, अभी मैं व्यस्त हूं जाओ, बादमें बात करेंगे।'

कालेजों-स्कूलोंका अपना मकान न होना और शिक्षकोंको वेतन न मिलना बिहारके लिए आम बात है। अन्य इलाकोंकी क्या बात, राजधानीके दर्जनों स्कूल-कालेज बिना भवनके हैं और शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियोंको कई वर्षोंसे वेतन नहीं मिला है। अभी पूरे राज्यके तमाम स्कूलों-कालेजोंके शिक्षक वेतनकी मांगके लिए आन्दोलनपर हैं और उनका आन्दोलन कई महीनोंसे चल रहा है। पिछले महीने प्रधान मन्त्री द्वारा 'सबके लिए शिक्षा' पर दिल्लीमें बुलाये गये मुख्य मन्त्री सम्मेलनमें बिहारके मुख्य मन्त्रीने स्वयं स्वीकार किया कि राज्यमें १३,००० भवनविहीन स्कूल हैं। हालांकि यह संख्या वास्तविकतासे कोसों दूर है लेकिन जाहिर है कि इस सूचीमें अस्तित्वहीन संस्कृत विद्यालय एक भी नहीं है।

राज्यके सारे संस्कृत विद्यालय ऐसे ही स्थानोंपर चल रहे हैं जहां सम्भ्रान्त लोग नहीं रहते और अगर उधरसे गुजरना भी हो तो नाक बन्द कर लेते हैं। विद्यालय चलानेवालोंको वैसी जगहोंपर भी खटालवालों और कूड़ा-कचरा फेंकनेवालोंके कड़े विरोधका सामना करना पड़ता है। अगर देहातमें हों तो संस्कृत शिक्षकोंको अपने जीवनयापनके लिए सम्पन्न गृहस्थोंका आश्रय लेना पड़ता है। विद्यालयके लिए कृपालु गृहस्थ अपने दालानका एक हिस्सा दे देते हैं जिसके एक कोनेमें 'पण्डीजी' की चौकी रहती है। भोजन और चौकीके एवजमें 'पण्डीजी' को आश्रयदाताके बच्चोंको सुबह-शाम पढ़ाना होता है।

राज्यके सारे संस्कृत विद्यालय ऐसे ही स्थानोंपर चल रहे हैं जहां सम्भ्रान्त लोग नहीं रहते और अगर उधरसे गुजरना भी हो तो नाक बन्द कर लेते हैं। विद्यालय चलानेवालोंको वैसी जगहोंपर भी खटालवालों और कूड़ा-कचरा फेंकनेवालोंके कड़े विरोधका सामना करना पड़ता है। अगर देहातमें हों तो संस्कृत शिक्षकोंको अपने जीवनयापनके लिए सम्पन्न गृहस्थोंका आश्रय लेना पड़ता है। विद्यालयके लिए कृपालु गृहस्थ अपने दालानका एक हिस्सा दे देते हैं जिसके एक कोनेमें 'पण्डीजी' की चौकी रहती है। भोजन और चौकीके एवजमें 'पण्डीजी' को आश्रयदाताके बच्चोंको सुबह-शाम पढ़ाना होता है।

राजधानीके एक मुख्य चौराहेके निकटवर्ती मुहल्लेका एक संस्कृत विद्यालय खुद अपनी कहानी कह रहा है। टूटी झोपड़ीमें चल रहे इस स्कूलके तीन तरफ खटाल हैं और एक तरफ है कचरागाह। इस विद्यालयकी संचालिका सह-प्रधानाध्यापिका विभाकुमारी सिन्हा बताती हैं- 'खटालवालोंके जिल्लत और ताने तो रोजमर्राकी बात है, इसकी परवाह की होती तो यह स्कूल ही नहीं बनता। संस्कृत पढ़ना-पढ़ाना इस राज्यमें अभिशाप है। चारों तरफ गोबर, गन्दे नाले, कचरोंकी सड़ांध और बीचमें स्थित है प्राथमिक सह-उच्च संस्कृत विद्यालयकी यह झोपड़ी, जिसका ३०० रुपया किराया श्रीमती सिन्हाको देना पड़ता है और जीविका चलानेके लिए झोपड़ीमें आटा-चक्की चलानेकी मजबूरी है। इधर हालमें हरिजन आदिवासी महिला कल्याणके नामपर कचरागाहका एक टुकड़ा इन्हें कार्यालयका सचिव होनेके चलते मिला है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। शुक्र है, इसका किराया श्रीमती सिन्हाको नहीं देना पड़ रहा है। हरिजन आदिवासियोंके कल्याणका दिन-रात ढिंढोरा पीटनेवाली बिहारकी जनता दल सरकारका ध्यान क्या इस ओर जायेगा? कमालकी बात तो यह है कि इस विद्यालयसे निर्गत प्रमाणपत्रोंको सरकारी मान्यता प्राप्त है लेकिन सरकारको प्रमाणपत्र निर्गत करनेकी प्रक्रियासे जूझनेवालोंके दोनों जूनकी रोटीकी चिन्ता नहीं है। इस विद्यालयमें अपने बच्चोंको भेजनेवाले इस मुहल्लेके निहायत ही गरीब तबकेके लोग हैं जिनमेंसे अधिकांश शुल्क जमा करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। जो थोड़ा-बहुत दे देते हैं, वही शिक्षकोंकी रोजी है।

ताजातरीन सूचनाओंके अनुसार अबतक ४१ संस्कृत शिक्षक भुखमरीके शिकार हो चुके हैं। बिहार संस्कृत शिक्षक महासंघके प्रवक्ता रामाश्रय चौधरीका कहना है कि जिनके पास अपने गांवमें थोड़ा-सा जमीन जाल है (हालांकि ऐसे शिक्षकोंकी संख्या बहुत कम है) उन्हें छोड़कर शेष शिक्षकोंके परिवार, बाल-बच्चोंके सामने तो भुखमरीकी स्थिति है ही। उनका आरोप है कि शिक्षामन्त्री डाक्टर रामचन्द्र पूर्वेने ५० बार समय निर्धारित करके बातचीत नहीं की। अन्य शिक्षकोंको बीच-बीचमें किसी न किसी कोषसे वेतन दे दिया जाता है लेकिन संस्कृत शिक्षकोंके बारेमें बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा जाता। इस सम्बन्धमें शिक्षामन्त्रीसे सम्पर्क स्थापित करनेकी कोशिश बेकार गयी।

संस्कृत शिक्षकोंने अपनी ओरसे

हाथ-पांव मारनेमें कोई कसर नहीं छोड़ी हैं- प्रधान मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव और केन्द्रीय मानव संसाधन विकासमन्त्री श्री अर्जुन सिंह भी इनके लिए मददगार साबित नहीं हुए। १९९१ और १९९३ में २ अक्तूबरको संस्कृत शिक्षकोंका

सरकारने केन्द्रीय मानव संसाधन विकासमन्त्रीकी बात गम्भीरतासे ली होती तो अबतक उनके पत्रका जवाब चला गया होता और यहां स्थिति यह है कि हर बार विधानमण्डलके दोनों सदनोंमें सबसे ज्यादा प्रश्न मानव संसाधन विकास

राजघाटपर सामूहिक उपवास चला और ८ अक्तूबर, '९१ को उनका प्रतिनिधिमण्डल प्रधान मन्त्रीसे मिला। श्री चौधरीके मुताबिक प्रधान मन्त्रीने संस्कृत शिक्षकोंकी दु:स्थितिपर काफी दु:ख और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि 'एक ओर तो राष्ट्रीय स्तरपर संस्कृत विद्वानोंका सम्मान कर हम इस भाषाकी प्रतिष्ठा बढ़ा

विभागके सम्बन्धमें पूछे जाते हैं जिनमें अधिकांश संस्कृत शिक्षकोंके वेतनसे जुड़ा होता है, लेकिन किसीका भी माकूल जवाब रामचन्द्र पूर्वेजी नहीं दे पाते। वैसे अल्पसंख्यक स्कूलोंकी दशा भी इससे बेहतर नहीं है जो और अचरजकी बात है क्योंकि जनता दल सरकार अपनेसे ज्यादा किसीको भी अल्पसंख्यकोंका शुभचिन्तक

रहे हैं, दूसरी ओर देशके अन्दर संस्कृत पढ़ानेवालोंकी यह दुर्दशा बड़े शर्मकी बात है।' उन्होंने इस सम्बन्धमें मानव संसाधन विकास मन्त्रालयसे बात करनेका आश्वासन भी दिया।

उसके पूर्व प्रतिनिधिमण्डल श्री अर्जुन सिंहसे मिला जिन्होंने बिहार सरकारके मानव संसाधन विकास विभागको लिखा कि संस्कृत शिक्षकोंके वेतनपर होनेवाले खर्चका ब्यौरा भेजा जाये। अगर बिहार

नहीं मानती।

बिहारमें एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा जो अगर केन्द्रके अधीन नहीं होता तो यहांके शिक्षक भी वेतनके लिए तरसते रहते। इस विश्वविद्यालयके स्नातकोत्तर छात्र कुलानन्द झाका कहना है- 'बाहरकी कौन कहे, घरमें भी लोग मनोबल गिराते हैं और हमेशा ताने मारते हैं- किसी स्कूल-कालेजमें पण्डीजी

बननेके सिवाय और बनोगे क्या?' ऐसे वातावरणमें भी छात्र पढ़ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

वास्तवमें सचाई यह है कि बिहारमें अबतक जितनी भी सरकारें बनीं, किसीने भी संस्कृत शिक्षाके विकासकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए श्री लालूप्रसादपर 'ब्राह्मण विरोधी' होनेका आरोप लगाकर सिर्फ इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। श्री लालूप्रसादको सत्तामें आये चार साल हुए और संस्कृत शिक्षक १९८१ से आन्दोलन कर रहे हैं जब मुख्य मन्त्री कांग्रेसी ही नहीं, ब्राह्मण भी थे। उस समयकी राजनीति दूसरी थी। लम्बे-चौड़े और आकर्षक घोषणाएं करके वाहवाही लूटी गयी लेकिन उनके कार्यान्वयनपर ध्यान नहीं दिया गया। संस्कृत शिक्षा बोर्डका गठन, प्रत्येक प्रखण्डमें ११ विद्यालय खोलने और सभी विद्यालयोंको राजकीय घोषित करनेका फैसला कांग्रेसी मुख्य मन्त्रियोंके समयकी बात है, लेकिन इन १४ वर्षोंमें ३७७६ संस्कृत विद्यालयोंकी प्रस्वीकृतिकी अधिसूचना जारी नहीं की गयी। लालूप्रसाद न तो बातचीत करते हैं न ही घोषणाएं।

इसीसे मिलती-जुलती स्थिति है संस्कृत अकादमीकी जिसे प्रतिवर्ष बिहार सरकारसे सिर्फ इतना ही मिलता है ताकि कार्यालयके मकानका किराया दिया जा सके। अकादमीके शोध अधिकारी विश्वेश चौधरी बताते हैं कि १९८७ में इसकी स्थापना संस्कृत भाषाके प्रचार-प्रसारके लिए की गयी थी, लेकिन अब तो बन्द होनेकी स्थिति है। इतने वर्षोंमें अकादमी कार्यालयके लिए भवनतक नहीं मिला। १९९० में किरायेकी अदायगी नहीं होनेके कारण मकानमालिकने कार्यालयमें तालाबन्दी कर दी। अकादमीके लिए दो लाख रुपयेकी सालाना स्वीकृति मिली हुई है लेकिन ९३-९४ में मात्र ५० हजार दिया गया जिससे स्थापना खर्चकी भी भरपाई नहीं हुई। १९९०-९१ में एक पैसा नहीं मिला। स्वीकृत पद हैं १४, कार्यरत हैं ९ और वे भी ३० महीनेसे बिना वेतनके काम कर रहे हैं। जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेशका अपना संस्कृत भवन है, जहां प्रतिवर्ष ११ लाख मिलता है। श्री मुलायम सिंह यादवने दूसरी बार मुख्य मन्त्री बननेके बाद यह राशि बढ़ाकर १५ लाख कर दी। श्री यादव भी लालूप्रसाद सरीखी पिछड़े वर्गकी राजनीति करते हैं लेकिन संस्कृत अकादमीको 'ब्राह्मणोंकी खाओ पियो संस्था' कहकर उन्होंने तिरस्कृत नहीं किया जो बिहारमें हो रहा है। बंगाली अकादमीके लिए अलबत्ता भूमि आवण्टित किया गया है। पिछले साल इस सम्बन्धमें केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और प्रधान मन्त्रीके संस्कृत सचिव विद्याधर शर्मा गुवेरीको लिखा गया। दोनों ओरसे संस्कृत अकादमी कर्मचारियोंको वेतन भुगतान न किये जानेका कारण पूछा गया और बिहार सरकारने चुप्पी साध ली। बिहारके शिक्षा विभागका कोई अधिकारी संस्कृत शिक्षकों और संस्कृत अकादमीके बारेमें कुछ भी स्पष्ट बतानेकी स्थितिमें नहीं है।

—शशिधर खां